न्यायमूर्ति पी. सी. जैन से पहले ए.सी.जे. और आई. एस. तिवाना

हरियाणा राज्य और अन्य,-अपीलकर्ता।

बनाम

श्री ओम प्रकाश और अन्य,-प्रतिवादी

1984 का पत्र पेटेंट अपील संख्या 1055

20 मई,1985

हरियाणा ग्रामीण विकास निधि अधिनियम (1983 का XII) - धारा 3 और 4 - अधिसूचित बाजार क्षेत्र में खरीदी या बेची गई या प्रसंस्करण के लिए लाई गई कृषि उपज की बिक्री आय पर उपकर लगाने वाला अधिनियम - डीलर द्वारा देय ऐसा उपकर - इस प्रकार एकत्र किया गया उपकर एक अलग बनता है विकास निधि - धारा 4(5) में निर्दिष्ट उद्देश्य जिसके लिए निधि खर्च की जानी है - इस तरह का अधिरोपण - चाहे कोई शुल्क हो - प्रतिदान का तत्व - उपकर के भुगतानकर्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ या सेवा - चाहे आवश्यक हो।

माना गया कि लेवी और के बीच सह-संबंध अपेक्षित है प्रदान की गई सेवाएँ सामान्य प्रकृति की हैं न कि गणितीय सटीकता की। बस इतना आवश्यक है कि ली की उगाही और प्रदान की गई सेवा के बीच उचित संबंध होना चाहिए। इस प्रकार बदले की भावना के सिद्धांत ने अपनी पवित्रता खो दी है और इसे एक पवित्र सिद्धांत बना दिया गया है। केवल इसलिए कि शुल्क का भुगतान करने वालों के अलावा अन्य लोगों को भी लाभ होता है, शुल्क के चरित्र में कमी नहीं आती है और शुल्क के भुगतानकर्ताओं को विशेष लाभ या लाभ सार्वजनिक हित में विनियमन के प्राथमिक उद्देश्य की तुलना में गौण भी हो सकता है। यह तेजी से महसूस किया जा रहा है कि सख्त अर्थों में प्रतिदान का तत्व हमेशा शुल्क के लिए अनिवार्य शर्त नहीं होता है और शुल्क के लिए प्रतिदान अनिवार्य रूप से होना चाहिए, इसमें व्यापक बदलाव आया है। इसलिए, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि शुल्क का भुगतान करने वालों को कुछ प्रत्यक्ष और विशेष लाभ प्रदान किया जाना है या यह कृषि उपज की खरीद या बिक्री के लेनदेन के संबंध में है या शुल्क का एक बड़ा हिस्सा है। जुटाए गए धन को इन दो उद्देश्यों के लिए खर्च करना होगा।

(पैरा 11)

माना गया कि उपकर लगाने वाला, यानी राज्य, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली राज्य की अन्य 80 प्रतिशत आबादी के साथ-साथ शुल्क का भुगतान करने वाले डीलरों के भारी बहुमत को असंख्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। 91 में से कम से कम 61 बाजार क्षेत्र जहां डीलर या शुल्क के भुगतानकर्ता रहते हैं या अपना व्यवसाय करते हैं, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं और उन क्षेत्रों का विकास हरियाणा ग्रामीण विकास निधि में निर्धारित नीति के अनुरूप किया जाएगा। अधिनियम, 1983 के अनुसार, डीलरों सहित उन क्षेत्रों की पूरी आबादी उन्हें प्रदान की जाने वाली सेवाओं से लाभान्वित होने या उनका आनंद लेने के लिए बाध्य है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, बेहतर संचार, खेतों से बाजारों तक सड़कों के निर्माण और उन क्षेत्रों में रहने वाले कृषि श्रमिकों की बेहतरी के साथ, न केवल 'अधिक खेती' का पोषित लक्ष्य पूरा होने की संभावना है। हासिल किया गया, लेकिन इससे कृषि उपज का कारोबार करने वाले डीलरों को फायदा होना तय है। इस प्रकार अधिनियम में सुझाए गए तरीके से निधि को खर्च करने से सीधे तौर पर सेवा मिलती है। डीलरों बाजार क्षेत्रों में रहने वाली आबादी के सामान्य जनसमूह के सदस्यों या एक हिस्से के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होने की भी संभावना है, जो राज्य की आबादी का लगभग 80 प्रतिशत है। वैसे भी, यह ऐसा मामला नहीं है जहां भुगतानकर्ता या डीलर यह शिकायत कर सकें कि भुगतान की गई फीस और उन्हें प्रदान की गई सेवाओं के बीच कोई आकस्मिक संबंध भी नहीं है।

(पैरा 12)

लेटर्स पेटेंट माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.पी. गोयल द्वारा 1984 की सिविल रिट याचिका।Vo.1118 में पारित आदेश दिनांक 13 अक्टूबर 1984 के खिलाफ लेटर्स पेटेंट के खंड एक्स के तहत अपील।

एच. एल. सिब्बल, ए.जी. हरियाणा निर्मल यादव, ए.ए.जी. के साथ। हरियाणा और बी.एस. गुप्ता, अधिवक्ता।

डी. वी. सहगल, वरिष्ठ अधिवक्ता। बी.एस. मलिक, एस.के. मित्तल, गोबिंद गोयल और बी.आर. महाजन, एडवोकेट, कुलदीप सिंह, सीनियर एडवोकेट के साथ। वी.एस. गारी, अधिवक्ता हस्तक्षेपकर्ता के साथ।

निर्णय

न्यायमूर्ति आई. एस. तिवाना

(1) इस लेटर्स पेटेंट अपील में उठाया गया एकमात्र विवाद हरियाणा ग्रामीण विकास निधि अधिनियम (1983 की संख्या 12) (संक्षेप में 'अधिनियम') की वैधता से संबंधित है। इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा बदले की भावना के खोखले सिद्धांत की कसौटी पर इसका परीक्षण किया गया है, जिन्होंने इसे और इसके तहत बनाए गए नियमों को भी असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया है। 1984 की 11 सिविल रिट याचिकाएं संख्या 2871, 3578 और 4213, 1985 की 960 से 963, 966, 967, 950, 907 का एक और सेट भी इसी आधार पर अधिनियम पर हमला करते हुए दायर किया गया है और इसमें शामिल पक्षों के विद्वान वकील हैं। इस बात पर सहमति हुई कि इन याचिकाओं का भाग्य निर्विवाद रूप से इस अपील के परिणाम पर निर्भर है। इस अपील में पक्षों के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्कों की सराहना करने के लिए, अधिनियम की मुख्य विशेषताओं का विचार होना आवश्यक है।

(2) (2) अधिनियम अधिसूचित बाजार क्षेत्र में खरीदी या बेची गई या प्रसंस्करण के लिए लाई गई कृषि उपज की बिक्री-आय के एक प्रतिशत की दर से यथामूल्य आधार पर उपकर लगाता है। यह अधिनियम की धारा 2 (सी) में परिभाषित अनुसार डीलर द्वारा देय है और इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति जो अधिसूचित बाजार क्षेत्र के भीतर खरीद, बिक्री, भंडारण या प्रसंस्करण के लिए किसी भी स्थान पर स्थापित करता है, स्थापित करता है या जारी रखने की अनुमति देता है। कृषि उपज की या अधिसूचित बाजार क्षेत्र में ऐसी कृषि उपज की खरीद, बिक्री, भंडारण या प्रसंस्करण। धारा 3(3) के अनुसार, डीलर अपने द्वारा भुगतान किए गए कर के बोझ को कृषि उपज के अगले खरीदार पर डालने का हकदार है और इसलिए, इसे कृषि उपज या सामान की लागत में जोड़ सकता है। इससे संसाधित, निर्मित किया जाता है। इस प्रकार एकत्र किए गए उपकर से हरियाणा ग्रामीण विकास निधि नामक एक निधि का गठन किया जाता है, जो राज्य सरकार के निपटान में है। जिन उद्देश्यों के लिए इस निधि को खर्च किया जाना है, वे अधिनियम की धारा 4(5) में निर्दिष्ट हैं। जो राज्य सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, अस्पतालों के विकास के संबंध में खर्च करने का अधिकार देता है। संचार के साधन, जल आपूर्ति, स्वच्छता और कृषि मजदूरों के कल्याण के लिए अन्य योजनाएं या ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित ऐसी कोई अन्य योजना। निःसंदेह इसके प्रशासन की लागत भी इसी निधि से वहन की जाती है। राज्य सरकार निधि से वित्त पोषित गतिविधियों की रिपोर्ट, निधि की प्राप्तियों और व्यय के अनुमानों के साथ राजपत्र में वार्षिक रूप से प्रकाशित करने के लिए बाध्य है खातों के स्टेटमेंट। अधिनियम में उल्लिखित बाजार और अधिसूचित बाजार क्षेत्र का वही अर्थ होना चाहिए जो पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961 में निर्दिष्ट है। यह स्वीकृत स्थिति है कि पूरे हरियाणा राज्य को अलग-अलग बाजार क्षेत्रों में अधिसूचित किया गया है और नहीं इसका एक भाग बाज़ार क्षेत्रों के बाहर रहता है।

(3) अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार ने नियम बनाए हैं, जिन्हें हरियाणा ग्रामीण विकास निधि नियम, 1984 के रूप में जाना जाता है। नियम 3(1) के अनुसार, डीलर पर उपकर लगाया जाता है और उप-नियम (2) के अनुसार इसके भुगतान की जिम्मेदारी डीलर पर है, जो खरीदार है, और यदि वह पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961 के तहत लाइसेंसधारी नहीं है, तो खरीदार विक्रेता है। जैसे ही कृषि उपज खरीदी या बेची जाती है, उपकर लगाया जाता है। नियम 4(1) के

अनुसार डीलर को फॉर्म 'ए' में अपना रिटर्न कर निर्धारण प्राधिकारी को अगले ही दिन अपनी खरीद और बिक्री दिखाते हुए जमा करना होगा, लेकिन किसी भी मामले में लेनदेन की तारीख के चार दिनों के बाद नहीं। इस नियम का उप-नियम (2) डीलर को उसके रिटर्न के आधार पर देय उपकर को नकद में जमा करने का आदेश देता है।

(4) याचिकाकर्ता-प्रतिवादी, जो पंजाब कृषि उपज और बाजार अधिनियम के तहत लाइसेंसधारी हैं, और अधिनियम के प्रयोजनों के लिए डीलर हैं, ने अधिनियम को दोहरे आधार पर लागू किया है, अर्थात, यदि अधिनियम द्वारा लगाया गया उपकर बिक्री पर कर है या कृषि उपज की खरीद, यह केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 15 का उल्लंघन करता है। और विकल्प में, यदि यह एक शुल्क है, तो जहां तक डीलरों का सवाल है, कोई सहायता नहीं है। जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है, यह बाद में उल्लिखित विवाद है जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश ने केवल कृष्ण पुरी बनाम पंजाब राज्य ए आई आर 1980 एस.सी. 1008 में सर्वोच्च न्यायालय पहले वाले को अस्वीकार करते हुए उनके आधिपत्य द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में स्वीकार कर लिया है।

(5) जैसा कि दलील दी गई है, राज्य का मामला यह है कि विचाराधीन उपकर एक कर नहीं है, बल्कि एक शुल्क है। इसे लागू करने के लिए त्रिस्तरीय दलील दी गई है, यानी (i) इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 से 48-ए में बताए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लगाया गया है, (ii) डीलर केवल एक संग्रहण एजेंट है , और कर का बोझ, वास्तव में, अगले खरीदार पर है, और ऐसे 80 प्रतिशत खरीदार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी से हैं; और (iii) कुल 91 अधिसूचित क्षेत्रों में से 61 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, और इस प्रकार डीलरों का भारी बहुमत है अधिनियम में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए निधि के उपयोग से उन क्षेत्रों के निवासियों या व्यापारियों को सीधे लाभ होता है। हालाँकि, इनमें से किसी भी दलील को आक्षेपित फैसले के तहत विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। पहली याचिका को इस आधार पर खारिज करते हुए कि याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई चुनौती नहीं है कि उपकर अनधिकृत उद्देश्यों के लिए लगाया गया था, उक्त याचिका मामले के निर्णय के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक थी; दूसरे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि के.के. पुरी के मामले (सुप्रा) में इसी तरह के तर्क को खारिज कर दिया गया था। तीसरी याचिका के अनुसार, जो कहा गया है वह इस प्रकार है:
"परिणामस्वरूप, भले ही 61 प्रतिशत डीलर और 80 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही हो, जैसा कि अधिनियम में परिभाषित है, फिर भी अधिनियम में उल्लिखित उद्देश्य जिसके लिए विकास निधि का उपयोग किया जाना है। जहां तक डीलरों और उस लेन-देन का संबंध है जिस पर अधिनियम में परिभाषित शुल्क लगाया गया है, कोई प्रतिशोध नहीं है।''

6) पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हम विद्वान एकल न्यायाधीश से असहमत होने के लिए राजी महसूस करते हैं।

(7) जैसा कि पहले संकेत दिया गया है, अधिनियम को असंवैधानिक और शून्य करार देते हुए, विद्वान न्यायाधीश ने के.के. पुरी के मामले (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के अपने आधिपत्य द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों पर बहुत अधिक भरोसा किया है। उन अवलोकनों से उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, उसे निम्नलिखित शब्दों में नोट किया गया है:
"केवल कृष्ण पुरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार (सुप्रा) यदि राशि वसूल की जाती है तो उसे अधिसूचित बाजार क्षेत्र में डीलरों को सेवा प्रदान करने के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए और इसका एक बड़ा हिस्सा डीलरों को दिखाया जाना चाहिए। इस प्रयोजन हेतु व्यय किया जाये। दूसरे, डीलरों को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ कृषि उपज की खरीद या बिक्री के लेनदेन के संबंध में होनी चाहिए। तीसरा, डीलरों को कुछ विशेष लाभ प्रदान किए जाने चाहिए जिनका उनके और लेनदेन के बीच सीधा उचित सह-संबंध हो, हालांकि डीलरों को संपूर्ण लाभ प्रदान करना आवश्यक नहीं हो सकता है।

वर्तमान मामले में इनमें से कोई भी परीक्षण संतुष्ट नहीं है। सड़कों, अस्पतालों, संचार के साधनों, जल आपूर्ति, स्वच्छता सुविधाओं के विकास और कल्याण पर खर्च की गई राशि
कृषि श्रम या ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी अन्य योजना के लिए बाजार क्षेत्र के डीलरों को कोई लाभ नहीं दिया जाता है और न ही इस उद्देश्य का बिक्री या खरीद से कोई संबंध है जिस पर शुल्क लगाया जाता है।"

(8) यद्यपि उपर्युक्त निष्कर्ष को दर्ज करते समय, विद्वान न्यायाधीश श्रीनिवास जनरल ट्रेडर्स और अन्य आदि बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य आदि में सुप्रीम कोर्ट के बाद के फैसले पर भी गौर किया। ए.आई.आर. 11983 एस.सी. 1 1246 जिसमें उनके लॉर्डशिप फिन के.के. पुरी के पिंजरे (सुप्रा) द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार किया गया और उन पर टिप्पणी की गई, फिर भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस बाद के निर्णय ने उस मामले में प्रतिपादित सिद्धांतों से कोई विचलन नहीं किया। के.के. पुरी के मामले (सुप्रा) में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा भरोसा किए गए निष्कर्षों को श्रीनिवास जनरल ट्रेडर्स के मामले (सुप्रा) में निम्नलिखित तरीके से संक्षेपित किया गया है: -
1. इसे कुछ निश्चितता, तर्कसंगतता या संभाव्यता की प्रबलता के साथ दिखाया जाना चाहिए कि प्राप्त शुल्क की राशि का एक बड़ा हिस्सा इसके भुगतानकर्ताओं के विशेष लाभ के लिए खर्च किया जाता है।
2. प्रदान की गई सेवाओं के लिए अनिवार्य रूप से शुल्क लगाया जाता है और इस प्रकार शुल्क का भुगतान करने वाले व्यक्ति और इसे लगाने वाले सार्वजनिक प्राधिकरण के बीच बदले की भावना का एक तत्व होता है।
3. सेवाओं का अर्थ लेनदेन, संपत्ति या संस्था के संबंध में सेवा है जिसके संबंध में उसे शुल्क का भुगतान करना पड़ता है।
ऐसा करने के बाद, उनके आधिपत्य ने देखा:
"अत्यंत सम्मान के साथ, विद्वान न्यायाधीश की इन टिप्पणियों को यूक्लिड के प्रमेयों के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, न ही किसी क़ानून के प्रावधानों के रूप में। इन टिप्पणियों को उसी संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें वे सामने आती हैं।"

उन्होंने आगे टिप्पणी की:
"केवल कृष्ण पुरी के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई उपरोक्त टिप्पणियों के बाध्यकारी प्रभाव के बारे में बार में काफी चर्चा हुई। अत्यंत सम्मान के साथ, केवल कृष्ण पुरी के मामले में निर्णय सामान्य प्रयोज्यता का कोई कानूनी सिद्धांत नहीं देता है।

(9) इस प्रकार यह स्पष्ट है कि के. यह स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि "इन टिप्पणियों को उसी संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें वे दिखाई देती हैं।" वैसे भी, हमें इन निर्णयों, यानी के. अमर नाथ ओम प्रकाश और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य ए.आई.आर. 1985 एस सी. 218 और द सिटी कॉरपोरेशन ऑफ कालीकट बनाम थाचम्बलैथ सदाशिवन और अन्य। 1985(1) स्केल 294 सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं निर्णयों पर विचार करने के बाद उन सिद्धांतों को निर्धारित किया है, जो हमारे विचार से, इस मामले के भाग्य को पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं। वास्तव में, विद्वान एकल न्यायाधीश को इन निर्णयों को संदर्भित करने का लाभ नहीं मिला क्योंकि ये अपील के तहत निर्णय की तुलना में बाद में सुनाए गए थे। हालाँकि, हम स्वयं को इन निर्णयों के अनुपात का पालन करने के लिए बाध्य पाते हैं, विशेष रूप से, जब विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा संदर्भित और चर्चा किए गए दो निर्णयों पर स्वयं उनके आधिपत्य द्वारा चर्चा और व्याख्या की गई हो।

(10) इन निर्णयों में से पहले एक में, उनके आधिपत्य ने यह राय देने के बाद कि के. "कोई नया सिद्धांत नहीं" निर्धारित किया गया। हमें फिर से इस निर्णय के विभिन्न हिस्सों का उल्लेख करने, के.
“अदालतों के निर्णयों को क़ानून के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। किसी क़ानून के शब्दों, वाक्यांशों और प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए, न्यायाधीशों के लिए लंबी चर्चा करना आवश्यक हो सकता है लेकिन चर्चा का उद्देश्य व्याख्या करना है न कि परिभाषित करना। न्यायाधीश क़ानून के शब्दों की व्याख्या करते हैं: उनके शब्दों की व्याख्या क़ानून के रूप में नहीं की जानी चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि के. "भुगतान अपने भुगतानकर्ताओं के विशेष लाभ के लिए खर्च किया जाता है" को संदर्भ से बाहर नहीं किया जाना चाहिए और इसे अलग से नहीं पढ़ा जाना चाहिए। बल्कि, इसे मामले के तथ्यों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए और विशेष रूप से उपर्युक्त उद्धरण से पहले वाले वाक्य में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें लिखा है:
“यह दूसरों को प्रदान की गई सेवाओं के साथ इतनी गहराई से जुड़ा या अंतर्संबंधित हो सकता है कि पूर्ण द्वंद्व और विश्लेषण करना संभव नहीं हो सकता है कि शुल्क के भुगतानकर्ताओं को कितनी विशेष सेवा प्रदान की गई और दूसरों को कितना अनुपात दिया गया।”

(11) दूसरे फैसले में कि सिटी कॉर्पोरेशन कालीकट के मामले (सुप्रा) में, जो अभी भी बाद के समय में है, श्रीनिवास जनरल ट्रेडर्स के मामले (सुप्रा) में राय देखने के बाद उनके आधिपत्य ने इस प्रकार फैसला सुनाया:
"इस प्रकार इस न्यायालय के हाल के कई निर्णयों से यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि प्रतिदान शुल्क में पारंपरिक अवधारणा परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और हालांकि शुल्क का इससे संबंध होना चाहिए प्रदान की गई सेवाएँ, या प्रदत्त लाभ, ऐसे संबंध का प्रत्यक्ष होना आवश्यक नहीं है, केवल आकस्मिक संबंध ही पर्याप्त हो सकता है। यह स्थापित करना आवश्यक नहीं है कि जो लोग शुल्क का भुगतान करते हैं उन्हें प्रदान की गई सेवाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करना चाहिए जिसके लिए शुल्क का भुगतान किया जा रहा है। यदि भुगतान करने वाला व्यक्ति शुल्क लगाने वाले प्राधिकारी से सामान्य लाभ प्राप्त करता है तो शुल्क एकत्र करने के लिए आवश्यक सेवा का तत्व संतुष्ट हो जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को शुल्क के भुगतान के लिए कोई विशेष लाभ या लाभ प्राप्त हो। (महत्व जोड़ें)
तथ्यों के आधार पर, यह एक ऐसा मामला था जहां नारियल की भूसी भिगोने के लिए भूमि और परिसर के उपयोग के लिए सिटी कॉरपोरेशन ऑफ कालीकट द्वारा लगाए गए लाइसेंस शुल्क को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि निगम द्वारा कोई सेवा प्रदान नहीं की गई थी या विशेष लाभ या अनुग्रह प्रदान नहीं किया गया था। उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि वे नारियल की भूसी भिगोने का व्यवसाय करते थे। उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त दो निर्णयों के आलोक में विवाद को खारिज करते हुए कहा:

“इन निर्णयों के अनुपात को लागू करने से यह निर्विवाद है कि अपीलकर्ता-निगम अपने परिचालन क्षेत्रों के भीतर व्यक्तियों को कई सेवाएं प्रदान कर रहा है और इसलिए शुल्क के रूप में लाइसेंस शुल्क लगाना पूरी तरह से उचित है। नारियल की भूसी भिगोने से दुर्गंध निकलती है और पर्यावरण प्रदूषित होता है। निगम सफाई सेवाएं प्रदान करके, शहर की सफाई के लिए अभियान चलाकर, बस्तियों को सहनीय बनाने के लिए सामान्य सेवा प्रदान कर रहा है, जिसके अन्य अपीलकर्ता लाभार्थी हैं। इस प्रकार शुल्क के रूप में लेवी उचित है।"

जैसा कि इस फैसले में पहले ही बताया गया है, दो मामलों का अनुपात, यानी श्रीनिवास जनरल ट्रेडर्स का मामला और मैसर्स अमरनैफी ओम प्रकाश के मामले (सुप्रा) को कानून की सही व्याख्या के रूप में स्वीकार किया गया था। जैसा कि पहले संकेत दिया गया था, उन दो बाद के निर्णयों में, के. इस निर्णय में आगे जो उजागर किया गया है वह यह है कि, "शुल्क का भुगतान करने वालों के अलावा अन्य लोगों को भी लाभ मिलता है, इससे शुल्क के चरित्र में कोई कमी नहीं आती है" और "शुल्क का भुगतान करने

वालों को विशेष लाभ या फायदा भी हो सकता है।" सार्वजनिक हित में विनियमन के प्राथमिक उद्देश्य की तुलना में गौण"। यह भी बताया गया है कि "यह तेजी से महसूस किया जा रहा है कि सच्चे अर्थों में प्रतिदान का तत्व हमेशा शुल्क के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है और शुल्क के लिए प्रतिदान अनिवार्य रूप से होना चाहिए, इसमें व्यापक बदलाव आया है। " इन निर्णयों से यह स्पष्ट है कि लेवी और अपेक्षित प्रदान की गई सेवाओं के बीच सह-संबंध सामान्य चरित्र का है न कि गणितीय सटीकता का। बस इतना आवश्यक है कि लेवी के बीच उचित संबंध होना चाहिए शुल्क और प्रदान की गई सेवाओं का। इस तरह से बदले की भावना के इस सिद्धांत ने अपना खोखलापन खो दिया है और इसे एक खोखला सिद्धांत बना दिया गया है जैसा कि इस फैसले के शुरुआती भाग में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार हम विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष को पाते हैं कि (i) शुल्क के भुगतानकर्ताओं को कुछ प्रत्यक्ष और विशेष लाभ प्रदान किया जाना है, (ii) यह कृषि की खरीद या बिक्री के लेनदेन के संबंध में होना चाहिए उत्पादन, और '(iii) उठाए गए शुल्क का एक बड़ा हिस्सा उपरोक्त दो उद्देश्यों के लिए खर्च किया जाना है, इस निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हैं।

(12) इस मामले के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के तथ्यों को लागू करते हुए, हम पाते हैं कि उपकर लगाने वाला, यानी राज्य, डीलरों या शुल्क के भुगतानकर्ताओं के भारी बहुमत को असंख्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। राज्य की अन्य 80 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। जैसा कि पहले ही बताया गया है, 91 में से कम से कम 61 बाजार क्षेत्र जहां डीलर या शुल्क के भुगतानकर्ता रहते हैं, या अपना व्यवसाय करते हैं, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं, और उन क्षेत्रों के विकास के अनुरूप हैं अधिनियम में निर्धारित नीति के अनुसार, डीलरों सहित उन क्षेत्रों की पूरी आबादी उन्हें प्रदान की जाने वाली सेवाओं से लाभान्वित होने या उनका आनंद लेने के लिए बाध्य है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, बेहतर संचार, खेतों से बाजारों तक सड़कों के निर्माण और उन क्षेत्रों में रहने वाले कृषि श्रमिकों की बेहतरी के साथ, न केवल 'अधिक खेती' का पोषित लक्ष्य पूरा होने की संभावना है। हासिल किया गया, लेकिन इससे कृषि उपज का सौदा करने वाले डीलरों, यानी याचिकाकर्ताओं को सीधे तौर पर फायदा होना तय है। इस प्रकार अधिनियम में सुझाए गए तरीके से निधि के व्यय से प्रत्यक्ष रूप से सेवा प्राप्त करने के अलावा, डीलरों को बाजार क्षेत्रों में रहने वाली आबादी के सामान्य जनसमूह के सदस्यों या एक हिस्से के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होने की भी संभावना है, जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है। राज्य की आबादी का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा हैं। वैसे भी, हम पाते हैं कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां भुगतानकर्ता या डीलर यह शिकायत कर सकें कि भुगतान की गई फीस और प्रदान की गई सेवाओं के बीच कोई आकस्मिक संबंध भी नहीं है, जैसा कि सिटी कॉरपोरेशन ऑफ कालीकट के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। उन्हें। इस प्रकार, हम विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष को उलट देते हैं, जैसा कि आक्षेपित निर्णय में दर्ज किया गया है।

(13) रिकॉर्ड को सीधे रखने के लिए हम यहां यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि एक चरण में, हरियाणा राज्य के विद्वान महाधिवक्ता श्री सिब्बल ने अधिनियम के दायरे को बनाए रखने या कर के रूप में भी उपकर लगाने की मांग की थी। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची ॥ में प्रविष्टि संख्या 52 के आलोक में, लेकिन जल्द ही उन्हें तर्क की निरर्थकता का एहसास हुआ और उन्होंने इसे छोड़ दिया। इस प्रकार हम मामले के उस पहलू की जांच करने के लिए बाध्य महसूस नहीं करते हैं; इससे भी अधिक, ऊपर हमारे द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के आलोक में।

(14) दर्ज किए गए कारणों से, इस अपील की अनुमति देते समय, हम विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द कर देते हैं और याचिका के साथ-साथ अन्य संबंधित याचिकाओं को भी खारिज कर देते हैं, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देते हैं।

एन.के.एस

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वहअपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अरुणिमा चौहान

प्रशिक्षु न्यशियक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पंचकुला, हरियाणा